POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 11 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

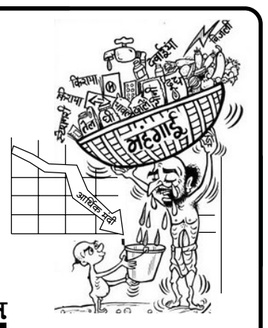

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2011 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

इस समय हमारे देश में ही नहीं करीब-करीब दुनिया के सभी मुल्कों में महंगाई का मुद्दा गर्माया हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के चलते विकास की गति कमजोर पड़ गई है और बहुत सी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूरोप के कई देशों की वित्तीय स्थिति चरमरा रही है। अमेरिका भी आर्थिक कठिनाइयों से रूबरू हो रहा है।

हमारे देश ने पिछली मंदी के असर को तो बर्दास्त कर लिया था, लेकिन लगने लगा है कि इस बार हम इसके असर से बच नहीं सकेंगे। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। हमारे यहां आर्थिक विकास की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है व बुनियादी उद्योगों की बढ़ोतरी में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। रुपए की कीमत कम हो जाने से पेट्रोल डीजल जैसी चीजों का दूसरे मुल्कों से मंगाना ज्यादा महंगा हो गया है।

ऐसी और भी कई वजह हैं जिनसे महंगाई पर रोक लगाना मुश्किल होता जा रहा है। खासतौर पर खाने-पीने की चीजों की बढ़ी कीमतों ने गरीबों का जीना भी दुश्वार कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तमाम उपायों के बावजूद मुद्रास्फीति की दर काफी ऊंचाई पर बनी हुई है।

'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभ कामनाएं!

भारत सरकार के सामने महंगाई पर काबू रखते हुए विकास की रफ्तार को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि घोटालों व भ्रष्टाचार के दुश्चक्र से घिरी सरकार अपने राजनीतिक बचाव में ज्यादा लगी है। नतीजतन वह महंगाई को कम करने के लिए न तो कानूनी और न ही नीतिगत फैसले ले पा रही है।

महंगाई के कारण हुई जेब खाली

आसमान छूती कीमतों के कारण भारतीय परिवारों को पिछले तीन सालों में करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से अतिरिक्त निकालने पड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि इस दौरान महंगाई अगर काबू में रहती तो देशवासियों की इतनी बड़ी रकम जाया नहीं होती। इस राशि से वे ढेर सारी दूसरी चीजों की खरीददारी कर सकते थे या बचत स्कीमों में निवेश कर अतिरिक्त लाभ कमा सकते थें।

हाल ही 'रिचर्ड फर्म क्रिसिल' द्वारा किए गए 'इन्फ्लेशन हट्र्स' नामक ताजा अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है। अध्ययन में बताया गया है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पाई और उसकी मार अभी भी जारी है। मुद्रास्फीति की दर 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान बढ़ कर 8 फीसदी से भी ज्यादा हो गई, जबकि उससे तीन साल पहले यह 5 फीसदी ही थी। इससे भारतीय मुद्रा की खरीद क्षमता घट गई और उन्हें यह नुकसान उठाना पड़ा। इस अवधि में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 11.6 फीसदी दर्ज की गई, जबकि गैर खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 5.7 फीसदी ही रही।

आर्थिक मंदी का पड़ेगा कम असर

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के मौजूदा दौर में, जब सारे राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है तब विश्वव्यापी मंदी का असर भारत पर भी आना लाजमी है। लेकिन इसका हम पर न्यूनतम असर होगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश मंदी के दौर से सफलतापूर्वक उबर जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है, यदि सभी राजनीतिक दल साथ दें तो विकास दर 9 फीसदी तक हो सकती है।

मंहगाई के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन इस समस्या पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा।क्योंकि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता विकास और आधारभूत ढांचे का विकास हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। बीमा, सार्वजनिक भंडारण, खाद्य सुरक्षा आदि विधेयक जल्द ही पारित होंगे। उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार व्यापार जगत और मौजूदा व्यापारिक ढांचे का पूरा ध्यान रखेगी और किसी परेशानी में नहीं आने देगी।

खाद्य पदार्थों की कीमतें चिंताजनक

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा ने माना है कि खाद्य पदार्थों में महंगाई का स्तर ज्यादा है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के सम्मेलन के समापन सत्र में इस पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई और केन्द्र सरकार ने कई उपाय किए हैं।

राज्य सरकारों को भी खाद्य पदार्थों पर से चुंगी और मंडी शुल्क पूरी तरह हटा देना चाहिए और पूरा नहीं हटा सकते, तो कम जरूर कर देना चाहिए। इससे महंगाई का प्रभाव कुछ तो कम हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस पर चर्चा करेंगे।

नहीं हो पा रहा महंगाई पर नियंत्रण

दुनिया में छा रही आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। एक ओर महंगाई 'सुरसा' की तरह मुंह फाड़ रही है तो दूसरी ओर विकास दर पर भी गलत असर पड़ रहा है। मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी दर्ज की गई है ।

औद्योगिक विकास दर भी हाल के जुलाई माह के लिए 3.3 फीसदी दर्ज की गई जो पिछले 21 माह में सबसे कम रही है। आर्थिक मंदी का असर रोजगार एवं उत्पादन पर भी पड़ रहा है। उद्योग और शेयर बाजार में निवेश घट रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2010 के बाद से 12 बार मंहगाई पर नियंत्रण के लिए प्रमुख ब्याज दरों व अन्य दरों में वृद्धि की है। इसके बावजूद महंगाई दहाई के अंकों के पास बनी हुई है।

सरकार की तमाम कोशिशें बेकार

सरकार की महंगाई रोकने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही है। पिछले दो माह में यह 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 9.78 फीसदी पर पहुंच गई है। यह पिछले एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई बढ़ने का अनुमान तो बाजार को पहले से था लेकिन ये आंकड़े उससे भी ज्यादा निकले।

दैनिक उपभोग की वस्तुओं की महंगाई दर में तो 1.25 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है और यह 12.50 फीसदी के भी पार पहुंच गई है। ईंधन और विद्युत ग्रुप की महंगाई दर 13 फीसदी के बेहद करीब पहुंच चुकी है।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बढ़ रही महंगाई पर फिक्र जाहिर की है। उनका कहना है कि दुनियाभर में कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर दबाव है।

कहां जाए आम आदमी

राजस्थान में बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को जायज ठहराने के लिए सरकार ही अब मंहगाई का सहारा ले रही है। जब महंगाई की बात आती है तो राज्य सरकार दूसरे राज्यों की तुलना करके अपने यहां कीमतें कम होने का दावा करने लगती है।

इसी तरह प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर वैट कम करने की बात की गई तो भी सरकार का यही जवाब रहा कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों से अभी भी वैट कम है।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि दरअसल सरकार की दृष्टि में आम आदमी कहीं है ही नहीं। एक तरफ 32 रुपए रोज खर्च के नाम पर गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का सहारा लेकर कंपनियों के घाटे के नाम पर पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है। सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ रही है।

रखना होगा बचत दर को बरकरार

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. विमल जालान ने कहा है कि वैश्विक मंदी से बचे रहने के लिए बचत दर को बरकरार रखने की जरूरत है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां बचत काफी अच्छी है और हम विदेशी निवेशकों पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि हमारी अर्थ व्यवस्था पर अभी मंदी का कोई खास असर नहीं है। लेकिन इस मंदी से हम अछूते भी नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती महंगाई से निपटना व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना है। हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन उनका सही इस्तेमाल होना जरूरी है। महंगाई पर लगाम लगाने के साथ-साथ हमें अपने उद्योग धंधों को मजबूत स्थिति में रखना होगा।

आर्थिक मंदी का है असर

वर्तमान में पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा हैं। इससे अमेरिका जैसे कई विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

आर्थिक मंदी के प्रभाव से उत्पादन, रोजगार, आमदनी और व्यापार-व्यवसाय में जहां लगातर गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और आर्थिक मंदी का असर व्यापार-व्यवसाय व बड़े बैंकों पर भी पड़ रहा है। महंगाई से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। बैंक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं। लोग वहां की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं।

आर्थिक विकास के मद्देनजर हमारे द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाये जाने के बाद आई पिछली मंदी के दौर को हमने जैसे-तैसे सहन कर लिया था, लेकिन इस बार अछूते नहीं रह सके। फलस्वरूप पूरा देश महंगाई की चपेट में है। बढ़ती मंहगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति का हमारे औद्योगिक व आर्थिक विकास पर असर पड़ रहा है।

हमारे वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी इसे मंजूर करते हुए कहते हैं कि बढ़ती मुद्रास्फीति चिंता की बात है।

कीमतों पर काबू पाना पहली प्राथमिकता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर डॉ. डी सुब्बाराव ने महंगाई दर 9.81 तक पहुंचने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर काबू पाना आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौति है। महंगाई पर काबू पाने के प्रयासों में अगर देश की विकास दर गिर जाए तो भी परवाह नहीं की जाएगी। आम आदमी के लिए वस्तुओं की दरें कम होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि विकास दर का बढ़ना।

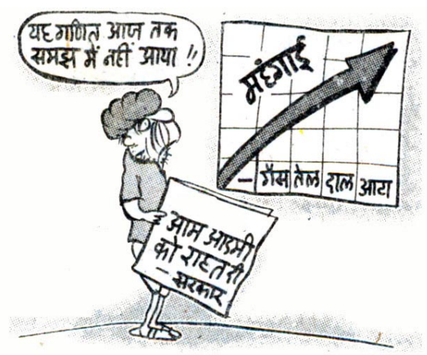

उन्होंने कहा सितम्बर में मुद्रा की दर 9.8 रही है तो खतरनाक सीमा में है। मार्च 2010 से अब तक 12 बार आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव किया है अगर ऐसा ठोस कदम नहीं उठाते तो महंगाई और रिकार्ड तोड़ देती। उन्होंने यह बात जयपुर में आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद कही। बैठक में महंगाई का मुद्दा प्रमुख रहा।

रोजगार के मुद्दे को मिले प्रमुखता

केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आर्थिक मंदी और महंगाई से स्थायी रूप से उबरने के लिए रोजगार का मुद्दा विकास की हर रणनीति में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात पिछले दिनों पेरिस में आयोजित जी-20 देशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कही।

खड़गे ने कहा कि भारत में श्रमिकों के अधिकारों पर आधारित कई नई सक्रिय श्रम बाजार नीतियों की शुरूआत की है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 जैसी नीतियां शामिल है।

भारत में हर साल 100 दिनों की मजदूरी की गांरटी देकर पांच करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया गया है। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से बेरोजगारी की समस्या से निपटने के तरीकों और उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था।

गरीबों को नही मिलता उनका हक

आम आदमी दाल रोटी की चिंता में पिसता जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकारें गरीबी मिटाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनाती हैं। विदेशों से इसके लिए मदद भी ली जाती है। बजट में इसके लिए खूब धन भी दिखाया जाता है। लेकिन बजट का बहुत बडा हिस्सा खर्च ही नहीं होता। जो खर्च होता है उसमें से भी प्रभावशाली पदों पर बैठे अधिकारी पैसा डकार जाते हैं। बहुत कम लोगों को इनका लाभ मिल पाता है।

गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाली आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, केरोसीन आदि भी कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाती है। सरकार दावा करती है कि वह राशन के जरिए गरीबों को सस्ता अनाज दे रही है। लेकिन यह बहुत कम गरीबों को मिल पाता है।

-रामस्वरूप दायमा
श्री माधोपुर, सीकर

फेंक देते हैं 10 से 30 फीसदी भोजन

बढ़ती महंगाई के इस दौर में भी पंचतारा होटलों, रिसोर्ट, सरकारी कार्यक्रमों व शादी-विवाह जैसे सामाजिक जलसों में तैयार किए गए भोजन का 10 से 30 फीसदी हिस्सा खराब होने के कारण फेंक दिया जाता है।

यह खुलासा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कराए जा रहे एक अध्ययन में हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल 230 लाख टन अनाज, 120 लाख टन फल तथा 210 लाख टन सब्जियों को फेंक दिया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार हर साल 58 हजार करोड़ रुपए के खाद्य पदार्थ बेकार हो जाते है।

'सामाजिक मेल-जोल के दौरान भोजन व दिखावटी व्यवहार से हुए अपव्यय का मूल्यांकन' नामक यह अध्ययन खाद्य मंत्री के.वी.थामस की पहल पर किया जा रहा है। मंत्रालय इस भोजन की बर्बादी को रोकने का कोई रास्ता खोजेगा।

क्यों बढ़ रही है खाद्यान्नों की कीमतें?

संसद में विपक्ष ने कहा है कि देश में खाद्यान्न के भंडार भरे पड़े हैं। सरकार का भी दावा है कि कृषि उत्पादकता बढ़ी है और सरकार के गोदामों में 6 करोड़ 55 लाख टन अनाज भरा पड़ा है। ऐसे हालात में खाद्यान्नों की महंगाई बढ़ने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। महंगाई ने आम आदमी की कमरतोड़ दी है। सभी खाद्य पदार्थों के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले तीन सालों से गेहूं, दालों, खाद्य तेलों, चीनी, दूध और चावल के बढ़ते मूल्यों से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री 'अपने हाथ ऊपर करते हुए' बड़े ही निराशाजनक बयान दे रहे हैं।

पूर्व वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा का कहना है कि सरकार गरीब के काम न आने वाली वस्तुओं के तो दाम घटा रही है, लेकिन उनके घर चलाने वाली चीजों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। जब तक सरकार कालाबाजारी, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीतियों को नहीं बदलेगी तब तक रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती नहीं होगी।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485